शहर के गंदे पानी के प्रदूषण से मुक्त होगी सोन नदी

शहर से गुजर कर सोन नदी में मिलने वाली सूखा-हिरन नदी के गंदे पानी को साफ करने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरु

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। शहर के गंदे पानी के प्रदूषण से सोन नदी मुक्त होगी। शहर से गुजर कर सोन नदी में मिलने वाली सूखा-हिरन नदी के गंदे पानी को साफ करने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरु है।

शहर के सूखा व हिरन नाले के गंदे पानी को शुद्ध करने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य समीपी गाड़ा खोह में शुरू हो गया है। नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए 3 लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को स्वीकृति मिली है। नालों का पानी शुद्ध करके सोन नदी में छोड़ने की व्यवस्था बनाई गई है। दरअसल नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के तहत अमृत योजना-2 में नगर पालिका परिषद सीधी के सूखा व हिरन नाले के गंदे पानी को शुद्ध कर सोन नदी में छोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम गाड़ा खोह में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने की अनुमति दी गई है। प्लांट में शहरी क्षेत्र से आने वाले गंदे पानी को साफ कर उसे सोन नदी में छोड़ा जाना है। नगर पालिका के अनुसार शासन स्तर से गत 15 अप्रैल को प्लांट की क्राइम-डिजाइन फाइनल हो जाने के बाद ठेका एजेंसी में ग्राम गाड़ा खोह में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बताया जाता है कि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक गड्ढे खोदने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया था। बताया गया है कि केन्द्रीय योजना के तहत अलग-अलग हिस्सों में दो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाना है। फिलहाल 5 एमएलडी वाले प्लांट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक एमएलडी के लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण नौगवां धीरसिंह गांव में कराया जाना है।

15 करोड़ की लागत से तैयार होंगे प्लांट

शहर के सूखाए हिरन व एक अन्य नाले का गंदा पानी सीधे सोन नदी में मिलता है। इन तीनों नालों का पानी शुद्ध करने के लिए दो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाए जाने हैं। इनमें से 5 एमएलडी प्लांट का निर्माण कार्य गाड़ा खोह गांव में पिछले माह से शुरू है। नगर पालिका अमले का कहना है कि नौगवां धीरसिंह एवं गाड़ा खोह में तैयार किए जाने वाले लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की कुल लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही समय-समय पर नगर पालिका के इंजीनियर मौका मुआयना कर गुणवत्ता का खास निगाह रख रहे हैं। निर्माण एजेंसी को एक वर्ष के अंदर दोनो लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार करने हैं।

प्रदूषण से सुरक्षित होगी सोन नदी

सोन नदी के प्रति हिंदू धर्म के लोगों की बड़ी आस्था है। यहां मकर संक्रांति अमावस्या व अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग स्नान कर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। स्वर्णकार समाज व व्यापारी वर्ग सहित अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा सोन नदी की महाआरती का भी आयोजन किया जा चुका है। ऐसे में नदी की मैली होती धारा लोगों के मन में चिंता और प्रशासन की हीला-हवाली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोन नदी न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि शहर की पेय जल व्यवस्थाए ग्रामीण जीवन और परिस्थितियों का भी प्रमुख आधार है। नदी के प्रदूषित होने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है और इसके आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।

इनका कहना है

लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण किया जाए, इसके लिए संविदाकार एवं संबंधित इंजीनियरों को निर्देशित किया गया है। **महमूद हसन, सीएमओ नगर पालिका परिषद सीधी**

श्रावण मास में ओम नम: शिवाय जप संकीर्तन का आयोजन

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। विश्व हिंदू महासंघ सीधी की ओर से श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही ओम नम: शिवाय जप संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है।

30 जुलाई से प्रारंभ जप संकीर्तन अनवरत रूप से 28 अगस्त तक चलेगा। संकीर्तन का आयोजन प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक किया जा रहा है। यह आयोजन विश्व हिन्दू महासंघ के जिला संयोजक बृजेश सिंह गोरे के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजन के दौरान यह संकीर्तन 30 अलग-अलग परिवारों के यहां चलना है। आज शाम 11 मुखी हनुमान जी पटेलपुल सीधी में ओम नम: शिवाय नाम जप संकीर्तन का आयोजन किया गया।

कलेक्टर ने कुसमी में सुनीं 78 आवेदकों की समस्याएं

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं सुशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुसमी जनपद पंचायत सभागार में मंगलवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्वयं उपस्थित होकर क्षेत्र के 78 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरतापूर्वक सुनीं।

कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ लिया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर राहत मिलना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर जनसुनवाई प्रारंभ होने से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित होगा, जिससे शासन-प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। जनसुनवाई में एसडीएम कुसमी सागर जैन, सीईओ जनपद पंचायत ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 को

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को टाटा कॉलेज सीधी में किया जा रहा है। जिला स्तर पर प्रथम आने वाली टीम को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली क्विज प्रतियोगिता में सहभागिता करने का अवसर मिलेगा।

मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को प्रस्तावित है जिसमें समस्त शासकीय एवं अशासकीय म.प्र. बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। जिसमें विद्यालय स्तर से 3-3 विद्यार्थियों का दल बनाया जाकर 188 विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कार्य भी पूर्ण किया गया है। जिले की पंजीकृत संस्थानों द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों को लेकर जिला स्तर पर 7 अगस्त को चयनित कार्यक्रम स्थल टाटा कॉलेज सीधी में उपस्थित होंगे। प्रतियोगिता दो चरणों में संपन्न की जावेगी। प्रथम चरण पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें लगभग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में प्रथम 6 टीमों का चयन किया जाएगा जिनके साथ द्वितीय चरण ऑडियो एवं वीडियो राउंड खेला जाएगा।

उच्च न्यायालय के निर्णय से छात्रसंघ चुनाव की जगी उम्मीद : अभिषेक

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। मध्यप्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बीच उच्च न्यायालय द्वारा छात्रसंघ चुनाव के संबंध में दिए गए निर्णय से विद्यार्थियों में एक बार फिर लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि चुनने की उम्मीद जगी है। छात्र नेता अभिषेक मिश्रा ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और नेतृत्व विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

अभिषेक मिश्रा ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने के केन्द्र नहीं हैं बल्कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। नियमित छात्रसंघ चुनाव होने से विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को संस्थागत स्तर पर प्रभावी ढंग से रखने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधित्व मिलता है। उन्होंने वर्ष 2017 के छात्रसंघ चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव आयोजित किए गए थे। श्री मिश्रा ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल पदाधिकारियों के चयन तक सीमित नहीं होते बल्कि इससे विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को नजदीक से समझने और उसमें सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिलता है। चुनावी प्रक्रिया से विद्यार्थियों में नेतृत्व, संवाद, संगठन क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। साथ ही महाविद्यालयों की शैक्षणिक एवं बुनियादी समस्याओं को प्रशासन के सामने व्यवस्थित रूप से रखने में छात्र प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर नहीं मिल पाया है।

विद्युत समस्याओं को लेकर कुबरी डीसी का घेराव, जेई ने समाधान का दिया आश्वासन

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। विद्युत वितरण केन्द्र कुबरी में विद्युत समस्याओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा आज सुबह 10 बजे से किए गए धरना-प्रदर्शन एवं घेराव के दौरान जेई बहरी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दो दिनों के भीतर खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। साथ ही कुशियारी में ट्रांसफार्मर से कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से पुन: जोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शेष मांगों का समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगले 15 दिनों के भीतर व्यापक जनआंदोलन और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि जेई बहरी ने भरोसा दिलाया कि निर्धारित समय से पहले ही सभी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से यज्ञराज साहू जनपद सदस्य कुबरी, सुदीप द्विवेदी करौंदी, रणजीत सिंह चंदेल दुअरा, मृत्युंजय प्रसाद गौतम कुबरी, राजबहोर द्विवेदी, छोटेराम द्विवेदी, रामगोपाल तिवारी, पुष्पराज शुक्ला, धीरेन्द्र सिंह पप्पू, प्रतीक द्विवेदी, संजय द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी, शुभम शुक्ला, मोतीलाल बंसल, बाबूलाल बंसल, जवाहर प्रसाद कोल, सीताराम साहू जिगनहा, रमेश तिवारी जिगनहा, मुकेश तिवारी, चंद्रमणि साहू, सियाराम साहू, मुन्नालाल साहू, चंद्रमणि कोल, गोविंद, शिवकरण, लल्लू, शिवबालक बंसल, शुभलायक, रामशरण, शिवकरण सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

सीएमएचओ और डीआईओ ने किया तेंदुआ, कुचवाही, भितरी स्वास्थ्य केन्द्रों का भ्रमण

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। इसी क्रम में सीएमएचओ डॉ.अशोक कुमार खरे के नेतृत्व में सिहावल विकासखंड के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

तेंदुआ केन्द्र में एनसीडी जांच, रजिस्टर संधारण और आईईसी में खामियां मिलने पर नाराजगी जताई गई। भ्रमण दल में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.नागेंद्र बिहारी दुबे एवं उपयंत्री अभिलाषा यादव भी शामिल थे। टीम ने नियमित टीकाकरण एवं दस्तक अभियान की मॉनिटरिंग की। उप स्वास्थ्य केन्द्र तेंदुआ में एएनएम प्रेमकली खटीक एवं साधना सिंह उपस्थित मिलीं। जांच में पाया गया कि एनसीडी कार्यक्रम के तहत हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज की जांच और रोकथाम के प्रबंध संतोषजनक नहीं थे। ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी, आरसीएच रजिस्टर अद्यतन नहीं था और स्टॉप डायरिया के लिए आईईसी प्रदर्शित नहीं था। इसके बाद दल ने उप स्वास्थ्य केन्द्र कुचवाही एवं पीएचसी भितरी का भी निरीक्षण कर टीकाकरण एवं अन्य सेवाओं का जायजा लिया। सीएमएचओ डॉ.खरे ने कहा कि शासन की मंशा है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने एवं योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

टोल कम्पनियां भारी मुनाफे में, फिर भी क्यों जारी है टोल वसूली : अजय

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछे कई सवाल

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिखकर भोपाल-देवास, जावरा-नयागांव तथा लेबड़-जावरा टोल परियोजनाओं को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

उन्होंने मंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए लिखित उत्तर तथा उपलब्ध ऑडिट रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि तीनों टोल कंपनियां लगातार अत्यधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं को घाटे का बताकर टोल वसूली जारी रखना तथ्य एवं अभिलेखों के विपरीत प्रतीत होता है। अजय सिंह ने कहा कि ऑडिट रिपोर्टों से स्पष्ट है कि कंपनियां निरंतर ऊंचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित कर रही हैं। यही कारण है कि इन कंपनियों के शेयर अनुबंध की भावना के विपरीत लगातार ऊंचे मूल्य पर बिके हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल-देवास टोल परियोजना की शेयर पूंजी के पुनर्गठन के दौरान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2023 में 10 रूपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य 126691 रूपये निर्धारित किया था। वहीं जावरा-नयागांव परियोजना में अशोका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने लगभग 287 करोड़ के शेयर 691 करोड़ में स्थानांतरित किए। इसके अतिरिक्त विदेशी निवेशकों द्वारा भी तीनों टोल कंपनियों में उल्लेखनीय निवेश किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कंपनियां घाटे में होतीं तो न तो उनके शेयर इतने ऊंचे मूल्य पर बिकते, न विदेशी निवेशक निवेश करते और न ही कंपनियां नियमित रूप से आयकर का भुगतान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय तथा शेयरधारकों को करोड़ों रुपये का लाभांश वितरित कर पातीं। कंपनियों द्वारा अर्जित भारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि परियोजनाएं लाभकारी हैं। अजय सिंह ने प्रश्न उठाया कि यदि सरकार अनुबंध की 26 प्रतिशत प्रमोटर शेयरधारिता जैसी महत्वपूर्ण शर्त में परिवर्तन कर सकती है तो लागत से कई गुना अधिक टोल वसूली होने की स्थिति में टोल समाप्त करने का निर्णय क्यों नहीं लिया जा सकता? उन्होंने कहा कि अनुबंध संपन्न होने के बाद परियोजना की लागत अथवा व्यय का पुनर्मूल्यांकन करने का कोई प्रावधान नहीं है। श्री सिंह ने विधानसभा प्रश्न क्र. 1270, दिनांक 3 मार्च 2023 के उत्तर का भी उल्लेख किया, जिसमें तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र का अनुबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

भइया सिंह के दाह संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, बड़े पुत्र ने दी मुखाग्नि

नवभारत न्यूज

मझौली 4 अगस्त। जिले के मझौली उपखंड के नगर परिषद मझौली वार्ड क्रमांक 11 निवासी मझौली क्षेत्र की शान अभयराज सिंह बाघेल गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए 3 अगस्त 2026 को 76 वर्ष की आयु में दिल्ली के निजी अस्पताल एम्स में अंतिम सांस ली।

उनके पार्थिव शरीर को मझौली लाया गया, जहां दाह-संस्कार झमाझम बारिश के बीच गृह निवास मझौली में किया गया। जहां लोगों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा। जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीधी चिंतामणि तिवारी, आनंद सिंह शेर, रामकुमार सिंह, राजकरण सिंह, सुधीन्द्र शुक्ला, वेंकटरमण सिंह, मदन मोहन तिवारी, यमुना प्रसाद वर्मा सहित क्षेत्र के लोग भारी संख्या में शामिल रहे। बताते चलें कि श्री सिंह ऐसे शख्सियत के इकलौते पुत्र थे जिनके नाम से ना केवल मझौली को जाना जाता था बल्कि दूसरे प्रदेशों में जब सीधी जिले का नाम बताया जाता था तो वहां के लोग कहा करते थे कि लाल कुंवर रामपाल सिंह वाली सीधी। इन्होंने भी अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश भर में अपनी अलग छवि और पहचान बने हुए थे। यही कारण रहा की मुखाग्नि में विंध्य क्षेत्र के लोग शामिल हुए।

सीईओ ने जनसुनवाई में 246 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। जिला पंचायत सीधी के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा ने मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 246 आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनीं।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी लेकर सभी मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाए तथा निर्धारित समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी : विकास

कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय कुसमी का किया औचक निरीक्षण, सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के दिए सख्त निर्देश

नवभारत न्यूज

सीधी 4 अगस्त। कलेक्टर विकास मिश्रा ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी (राजस्व) कार्यालय एवं तहसील कार्यालय कुसमी का औचक निरीक्षण कर राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के संधारण, लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भ्रमण क्षेत्र से संबंधित सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में प्राप्त सभी लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न होकर गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक होना चाहिए, जिससे नागरिकों को वास्तविक राहत मिल सके। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा के लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण करते हुए

अनावश्यक विलंब समाप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए फार्मर आईडी का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पात्र किसानों का पंजीयन अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यालयों में साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं नागरिक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ संवेदनशील, शालीन एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अंत में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें तथा सभी प्राथमिकता वाले कार्यों में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कुसमी सागर जैन, सीईओ जनपद पंचायत ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

लोक सेवा केन्द्र का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र कुसमी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने केन्द्र में नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं, लंबित आवेदनों तथा सेवा वितरण की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएं तथा अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा केन्द्र आमजन और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, पारदर्शी एवं सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।